

उत्तराखण्ड में 1 जुलाई से लागू होगी नई शिक्षा नीति

चर्चा में क्यों?

13 मई, 2022 को उत्तराखण्ड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सहि रावत ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पौड़ी के सम्मेलन में बताया कि राज्य में इस वर्ष 1 जुलाई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही उत्तराखण्ड एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राथमिक से माध्यमिक कक्षाओं तक का पाठ्यक्रम इसी शिक्षा नीति के तहत तैयार करने के साथ ही राज्य सरकार 12,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने जा रही है।
- गौरतलब है कि के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2020 में लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 1986 की शिक्षा नीति में व्याप्त कमियों को दूर कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कार्यांतरण करना है।
- इसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं-
- वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (**Gross Enrolment Ratio – GER**) को 100% करना।
- केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 6% सार्वजनिक व्यय करना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (**Gross Enrolment Ratio**) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करना।